करने के लिए कर सकें। यह योजना नाबार्ड द्वारा तैयार की जा रही है और निकट भविष्य में बैंकों को परिचालित कर दिए जाने की आशा है।

इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी निधि की आवश्यकता नहीं होगी।

**ऋण कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह**

*597. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
**श्री बरजिन्दर सिंह:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1998 के दैनिक "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "आर०बी०आई० टैल्स गवर्नमेंट टू कट बा रोइम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को सलाह दी है कि वह अपने ऊपर उधार ली गई राशि की मात्रा में कमी लाये;

(ग) यदि हां, तो जुलाई, 1998 के प्रथम सप्ताह में सरकार पर ऋण की कितनी राशि बकाया थी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि के कारण देश में ब्याज की दर में वृद्धि होने की संभावना है?

**वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सरकारी उधारों से संबंधित मामलों पर लगातार परस्पर कार्यात्मक व्यवहार होता रहता है। केन्द्रीय सरकार के सकल उधारों का आकार भारत सरकार के बजटीय परिचालनों को प्रतिबिम्बित करता है। किसी वर्ष के लिए सकल बाजार ऋण कार्यक्रम पर निर्णय करते समय, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि , बचतों और निवेश में वृद्धि और विभिन्न वित्तीय लिखतों के माध्यम से संसाधन संग्रहण के रूप में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली से सहायता जैसे संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार द्वारा बाजार से संसाधन संग्रहणों के महत्वपूर्ण वृहत-आर्थिक निहितार्थ होते हैं, जांच भारत सरकार और भारतीत रिजर्व बैंक के बीच पारस्परिक परामर्शों के माध्यम से की जाती है।

वर्ष 1997-98 (संशोधित अनुमान) के अन्त में बाजार ऋणों की राशि, 2,17,501 करोड़ रुपए थी। चालू वित्तीय वर्ष में 4 जुलाई तक दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार का सकल बाजार उधार 40,530 करोड़ रुपए बनता था।

(घ) ब्याज दर में घट-बढ़ वित्तीय प्रणाली में नकदी निधि की स्थिति, ऋणयोग्य निधियों के लिए मांग और विदेशी मुद्रा बाजार में घटनाक्रम जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। सरकारी उधार कार्यक्रम को चरणबद्ध करने का उद्देश्य है दीर्घावधिक ब्याज दरों पर प्रतिकूल प्रभावों को कम से कम करना।

**Financial aid for enhancement of Cargo Handling Facilities of Port.**

*598. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA' Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any plan to add about 159 million tonnes of capacity for cargo handling at the ports;

(b) if so, whether funds required for the purpose have been estimated; and

(c) if so, the source of such funds?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBIDURAI) (a) to (c) Yes Sir. In addition to the schemes aggregating to 37 million tonnes of capacity carried over from the 8th Five Year Plan, new schemes for 133 million tonnes of capacity creation are proposed to be started during the 9th Plan period. The requirement of funds for the 9th Plan has been estimated to be Rs. 14, 908 crores. Out of this, an outlay of Rs. 7215 crores has been provided for in the 9th Plan. The balance funds are proposed to be raised from private sector

**Declining value of rupee**

*599. SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the slide in the value of rupee against dollar continued since November, 1997 from Rs. 36.54 to 42.37 per dollar as on 17th June, 1998: